

ब्यूज टुडे

भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के फूक निर्णय को खारिज कर दिया

हेग स्थित CoA का निर्णय: कोर्ट ने कहा कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) को “स्थगित” रखने से जम्मू और कश्मीर की किशनगंगा एवं रतले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादों पर कोर्ट द्वारा निर्णय देने की अधिकारिता (authority) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह घोषणा की थी कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को नहीं रोकता, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा।

विवाद की पृष्ठभूमि

सिंधु जल संधि (IWT): इस संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।

नदी जल के बंटवारे के प्रावधान:

- पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी का समस्त जल भारत को आवंटित किया गया है।
- पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब का जल ज्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है।

विवाद:

- दोनों देशों के बीच किशनगंगा (झेलम की सहायक नदी पर) और रतले (चेनाब पर) जलविद्युत परियोजनाओं की डिजाइन संबंधी विशेषताओं को लेकर असहमति है।
- वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने डिजाइन संबंधी विशेषताओं पर आपत्ति जताई थी तथा विश्व बैंक के माध्यम से तटस्थ विशेषज्ञों की मांग की थी।
- वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने विवाद को हल करने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा निर्णय का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा विवाद को हल करने की मांग की थी।
- वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति की।
- भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ प्रक्रिया को स्वीकार किया।

भारत ने इस निर्णय को क्यों खारिज किया:

- कोर्ट की वैधता पर सवाल: भारत का कहना है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन “अवैध रूप से” हुआ है और यह 1960 की सिंधु जल संधि का खुला उल्लंघन है। इसलिए, इसकी कार्यवाही और निर्णय “अवैध तथा स्वयं में निरर्थक” हैं।
- संधि को स्थगित करने का संप्रभु अधिकार: भारत ने कहा कि वह एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है और इसलिए संधि को स्थगित करना उसका वैध अधिकार है।

3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र



स्थायी सिंधु आयोग: संधि के कार्यान्वयन से जुड़े विवाद को हल करने के लिए स्थायी सिंधु आयोग को हर साल कम-से-कम एक बार बैठक करनी आवश्यक है।



तटस्थ विशेषज्ञ: जल-बंटवारे पर अनसुलझे मतभेदों को निपटाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं।



कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन: विवाद समाधान के लिए एक सात सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) का प्रावधान किया गया है।

“भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य में बदलाव” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें ज्ञान-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत के कौशल परिदृश्य की समीक्षा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

भारत का कौशल परिदृश्य

- कम दक्षता वाले व्यवसाय: वर्ष 2023-24 में भारत का लगभग 88% कार्यबल कम-दक्षता वाले कार्यों में लगा हुआ था।
- बेमेल कौशल: कई कामगार ऐसे कार्यों में लगे हैं, जो उनकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं होते। इसका कारण यह है या तो उनकी योग्यता अधिक होती है या कम होती है।
- संरचनात्मक मुद्दे:
 - कम-कौशल वाले कार्यों में अधिक शिक्षित लोगों का होना इस तथ्य को दर्शाता है कि उच्च-कौशल वाली नौकरियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।
 - वहीं, कम शिक्षित लोगों का उच्च-कौशल वाली नौकरियों में होना इस तथ्य को दर्शाता है कि कम आय वालों और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुंच की भारी कमी है।
- उच्च-कौशल वाली नौकरियों में कौशल की कमी: इन भूमिकाओं के लिए आवश्यक शिक्षा की कमी वाले कई लोग हैं।

बेमेल कौशल का प्रभाव

- आर्थिक उत्पादकता में गिरावट: अधिक शिक्षित लोग जब कम-कौशल वाले कार्यों में लगते हैं, तो उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। वहीं, कम शिक्षित लोग उच्च-कौशल वाली नौकरियों में संघर्ष करते हैं।
- मानव संसाधन का अक्षम उपयोग: कौशल और नौकरी के बीच असंतुलन से श्रम बाजार की क्षमता घटती है और नवाचार में बाधा आती है। साथ ही, देश की जनसांख्यिकीय शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
- सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बाधा: यह असंतुलन पहले से मौजूद असमानताओं को और बढ़ाता है, जिससे गरीब वर्गों के लिए ऊपर उठने के अवसर कम हो जाते हैं। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में भी वृद्धि होती है।
- प्रवासन और प्रतिभा पलायन: बेहतर अवसरों की कमी लोगों को दूसरे राज्यों या देशों की ओर पलायन के लिए मजबूर कर सकती है।

सिफारिशें

- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण (TVET) में सुधार करना: पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों की बदलती जरूरतों एवं नई तकनीकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- कौशल की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक मानक तंत्र स्थापित करना: यह कार्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेपों में मदद करेगा।
- उद्योगों की भागीदारी और जवाबदेही: उद्योगों को प्रमाणित कुशल लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और बाजार के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
- आजीवन सीखने को बढ़ावा देना: कर्मचारियों को निरंतर कौशल विकास (स्किलिंग), कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग), और नए कौशल सीखने (रीस्किलिंग) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इससे नौकरी की बदलती मांगों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

भारत के बाह्य (विदेशी) ऋण में वृद्धि दर्ज की गई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बाह्य (विदेशी) ऋण मार्च 2025 में 736.3 बिलियन डॉलर हो गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 67.5 अरब डॉलर अधिक है। इसमें मूल्यन प्रभाव (Valuation effect) यानी विनिमय दर में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है।

यहां मूल्यन प्रभाव से आशय भारतीय रुपये की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि (अधिमूल्यन) है।

RBI रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP)-बाह्य (विदेशी) ऋण अनुपात: यह अनुपात मार्च 2024 के 18.5% से बढ़कर मार्च 2025 में 19.1% हो गया।
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण: दीर्घकालिक ऋण आंशिक रूप से बढ़कर 601.9 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी आंशिक रूप कम होकर 18.3% हो गई।
- बाह्य ऋण के घटक: भारत के कुल बाह्य ऋण में 54.2% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर सबसे बड़ा घटक बना रहा। इसके बाद भारतीय रुपये (31.1%), जापानी येन और विशेष आहरण अधिकार (SDRs) में लिए गए ऋण का स्थान रहा।
- विदेशी ऋण लेने वाली संस्थाएं: कुल बाह्य ऋण प्राप्त करने वालों में गैर-वित्तीय कंपनियों (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी 35.5% रही। इसके बाद जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों (27.5%) और सरकार (22.9%) का स्थान है।
- ऋण साधन (Debt Instrument): भारत के कुल बाह्य ऋण में उधारी (34%) सबसे बड़ा घटक बना रहा। इसके बाद मुद्रा और जमा (अनिवासियों द्वारा) की हिस्सेदारी है।
- ऋण भुगतान: मूलधन और ब्याज भुगतान में 0.1% की आंशिक गिरावट दर्ज की गई।

बाह्य (विदेशी) ऋण क्या है?

- बाह्य ऋण वास्तव में किसी अन्य देश से अलग-अलग स्रोतों से लिया गया ऋण है।
- विदेशी ऋण के स्रोत: विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे-IMF विश्व बैंक) और अन्य देशों की सरकारें।

बढ़ते बाह्य (विदेशी) ऋण से जुड़ी चिंताएं



ऋण और ब्याज के भुगतान का बोझ

चूंकि, बाह्य ऋण अक्सर विदेशी मुद्राओं में लिया जाता है, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से ऋण भुगतान की लागत बढ़ जाती है।



बढ़ती मुद्रास्फीति

लंबे समय तक उच्च मुद्रास्फीति ब्याज दरों को बढ़ाती है, संवृद्धि दर को कम कर देती है, और ऋण-जीडीपी अनुपात को बढ़ा देती है।



उत्पादक कार्यों में निवेश में कमी होना

उच्च बाह्य ऋण की वजह से मूलधन और ब्याज भुगतान में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। इससे अवसंरचना, स्वास्थ्य - देखभाल और शिक्षा पर सरकारी व्यय कम हो जाता है।



भुगतान संतुलन पर प्रभाव

लगातार बढ़ता बाह्य ऋण चालू खाता घाटे को बढ़ाता है और बाह्य क्षेत्रक (व्यापार-निवेश) को अस्थिर करता है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24) जारी की गई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्रक के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल उत्पादन मूल्य (GVO): वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच (स्थिर कीमतों पर) इसमें लगातार 54.6% की वृद्धि हुई है। साथ ही, सकल मूल्य वर्धन (GVA) में (वर्तमान कीमतों पर) लगभग 225% की बढ़ोतरी हुई है।
- फसल क्षेत्रक (Crop Sector): वर्ष 2023-24 में कुल कृषि GVO में सबसे बड़ा योगदान फसलों (लगभग 54.1%) का रहा।
 - उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है।
 - वर्ष 2023-24 में सभी अनाजों के GVO में केवल धान और गेहूं का योगदान लगभग 85% रहा है।
- फूलों की खेती (Floriculture): वर्ष 2011-12 की तुलना में 2023-24 में इसका GVO लगभग दोगुना होकर 28.1 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया था।
- कंडीमेंट्स (चटनी, सॉस आदि) और मसाले:
 - मध्य प्रदेश सबसे बड़ा योगदानकर्ता (19.2%) है।
 - इसके बाद कर्नाटक (16.6%) और गुजरात (15.5%) हैं।
- मात्स्यिकी और जलीय कृषि (Fishing & Aquaculture):
 - इनका कुल योगदान 2011-12 में 4.2% था, जो 2023-24 में बढ़कर 7.0% हो गया।
 - मीठे पानी की मछलियों (inland fish) की हिस्सेदारी घटकर 50.2% हो गई है, जबकि समुद्री मछलियों (marine fish) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का महत्त्व

- GDP में योगदान: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का देश की कुल GDP में लगभग 16% का योगदान था।
- रोजगार का साधन: यह क्षेत्रक देश की लगभग 46.1% आबादी को आजीविका प्रदान करता है।
- मुख्य चुनौतियां:
 - प्रति इकाई भूमि कम उत्पादन क्षमता;
 - किसानों की आय का कम स्तर;
 - जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन;
 - जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं जैसे- सूखा, बाढ़ आदि।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए सरकारी पहलें:

- कृषि निवेश कोष (₹1 लाख करोड़): फसलों की कटाई के बाद की प्रक्रिया (जैसे भंडारण व प्रोसेसिंग) के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने हेतु यह कोष बनाया गया है।
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: खेती में डिजिटल तकनीकों (जैसे ड्रोन, डेटा, ऐप्स आदि) को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: इसका उद्देश्य मत्स्यन क्षेत्रक को औपचारिक बनाना और मत्स्यन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन प्रदान करना है।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- अन्य प्रमुख योजनाएं: मत्स्यन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष; प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) आदि।

मेडा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में पिछले दशक में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई

भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में यह वृद्धि मुख्य रूप से शुरुआती चरण में फंडिंग, भारत में डिजिटल यूजर्स की संख्या तथा मेट्रो के साथ अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण हुई है।

स्टार्ट-अप की परिभाषा:

- ▶ ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), जिसका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से कम हो।
- ▶ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों तक किसी कंपनी को स्टार्ट-अप माना जाता है।

भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास के लिए उत्तरदायी कारक

- ▶ AI को अपनाने में तेजी: 70% स्टार्ट-अप्स अपने व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल कर रहे हैं।
 - ⊕ केवल मार्केटिंग क्षेत्र में ही AI अपनाने वाले 87% उद्यमियों ने नए ग्राहक जोड़ने या नई बिक्री में लागत में सुधार दर्ज किए हैं।
- ▶ विदेशों में विस्तार: 50% स्टार्ट-अप्स संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े वैश्विक बाजारों को लक्षित कर रहे हैं।
- ▶ ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी माध्यमों का उपयोग: दो-तिहाई से अधिक स्टार्ट-अप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों का उपयोग करके ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए- डिजिटल विज्ञापन या रील्स के जरिए ग्राहक ऑनलाइन उत्पाद खोजते हैं, लेकिन महंगी खरीदारी के लिए स्टोर पर जाते हैं।
- ▶ टियर-2 और टियर-3 बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना: लगभग सभी स्टार्ट-अप्स अब छोटे शहरों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़े स्टार्ट-अप्स विशेष रूप से व्हाट्सएप या क्षेत्रीय इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इन शहरों में जल्दी प्रवेश कर रहे हैं।

भारत में विकसित होता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:

- ▶ स्टार्ट-अप्स की संख्या में वृद्धि: पूंजी प्राप्त होने और अनुकूल सरकारी नीतियों की वजह से स्टार्ट-अप्स की संख्या में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2024 में 1.5 लाख से अधिक हो गई।
 - ⊕ इनमें से 51% स्टार्ट-अप्स गैर-मेट्रो शहरों से हैं।
- ▶ भारतीय यूनिफॉर्म का संयुक्त वैल्यूएशन 380 बिलियन डॉलर से अधिक है।
 - ⊕ यूनिफॉर्म वास्तव में निजी स्वामित्व वाले ऐसे स्टार्ट-अप्स हैं, जिनका वैल्यूएशन (कुल आर्थिक मूल्य) 1 अरब डॉलर से अधिक है।
- ▶ वैश्विक रैंकिंग: भारत हरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025 में तीसरे स्थान पर है। यह स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को दर्शाता है।

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा



स्टार्ट-अप इंडिया

उद्देश्य: नवाचार को बढ़ावा देना और देशभर में अनुकूल स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण करना।



स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड (SISFS)

उद्देश्य: स्टार्ट-अप्स को विभिन्न चरणों जैसे कि उत्पाद का विचार, प्रोटोटाइप विकास और बाजार में प्रवेश के लिए सहायता प्रदान करना।



फंड ऑफ फंड्स (FFS)

उद्देश्य: स्टार्ट-अप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए देश में ही पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना।



क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)

उद्देश्य: DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को दिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।



अटल नवाचार मिशन (AIM)

उद्देश्य: अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्ट-अप हब (MSH)

प्रौद्योगिकी के हितधारकों को एकजुट करके और नवाचार को बढ़ावा देकर एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना।

नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत का भविष्य बनाना

अन्य सुर्खियां



भगवान जगन्नाथ रथ-यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं।

भगवान जगन्नाथ रथ-यात्रा के बारे में

- ▶ यह एक हिंदू त्योहार है और इसका ओडिशा के पुरी शहर में प्रतिवर्ष आयोजन होता है।
- ▶ इसमें प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है।
- ▶ यह त्योहार आषाढ़ महीने (जून-जुलाई) के दूसरे दिन शुरू होता है।
- ▶ लगभग एक सप्ताह बाद, भगवान जगन्नाथ के रथ बाहुड़ा यात्रा के द्वारा मुख्य मंदिर में वापस लौट आते हैं।



आदि कर्मयोगी

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम के बारे में

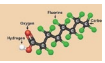
- ▶ लक्ष्य: ऐसे प्रेरित अधिकारियों और चेंजमेकर्स का एक समूह तैयार करना, जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हों।
- ▶ उद्देश्य: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षकों और मास्टर-ट्रेनर्स का एक बैंच बनाकर लगभग 20 लाख फील्ड-स्तरीय हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना।
- ▶ यह कार्यक्रम फील्ड-स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिसमें नागरिक-केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
- ▶ लक्ष्य: 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुंचना।



चालू खाता शेष (Current Account Balance)

भारत का 'चालू खाता शेष' वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4) में 13.5 अरब डॉलर (GDP का 1.3%) के अधिशेष में रहा।

- इसके कारण भारत का वार्षिक चालू खाता घाटा (CAD) घटकर 23.3 अरब डॉलर (GDP का 0.6%) हो गया। यह घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में 26 अरब डॉलर (GDP का 0.7%) का था।
- वार्षिक स्तर पर भारत में आमतौर पर व्यापार घाटा दर्ज किया जाता है।
- चालू खाता शेष क्या है?
- यह किसी देश और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में वस्तुओं, सेवाओं, आय और चालू खाता अंतरण (Current Transfers) के लेनदेन को मापता है।
- चालू खाता शेष किसी देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP) का एक प्रमुख घटक है।
- चालू खाते के प्रमुख घटक हैं: वस्तुएँ, सेवाएँ, आय और चालू खाता अंतर।



पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल पदार्थ (PFAS)

शोधकर्ताओं ने लगभग 20 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो PFAS को अपघटित करने में सक्षम हैं। PFAS के बारे में

- ये ऐसे रसायन हैं जिनमें कार्बन-फ्लोरीन (C-F) बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और आसानी से नष्ट नहीं होता।
- ये रसायन ग्रीस, तेल, पानी और उच्च तापमान का सामना करने में सक्षम होते हैं।
- उपयोग: कुकवेयर, फूड पैकिंग, फूड प्रोसेसिंग उपकरण, कपड़े, पेंट्स, फोम्स, आदि में।
- प्रभाव: ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे हवा, जल और मृदा प्रदूषित होती है तथा मनुष्यों तथा इंसान और जानवरों में बायोएक्यूमुलेशन (जैव-संचयन) के माध्यम से जमा हो जाते हैं।
- बायोएक्यूमुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और जीवों के शरीर में धीरे-धीरे जमा होते जाते हैं।

IBAT

IBAT एलायंस

IBAT एलायंस ने 2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना कर दिया है। यह बढ़ा हुआ निवेश तीन प्रमुख वैश्विक जैव विविधता डेटासेट का समर्थन करेगा।

- संरक्षित क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस,
- IUCN रेड लिस्ट,
- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का विश्विक डेटाबेस
- IBAT एलायंस के बारे में
- मुख्यालय: यूनाइटेड किंगडम।
- स्थापना: 2008 में हुई।
- यह दुनिया के चार सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संरक्षण संगठनों का एक गठबंधन है।
- ये चार संगठन हैं: बर्डलाइफ इंटरनेशनल; कंजर्वेशन इंटरनेशनल; प्रकृति संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय संघ; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र।
- मिशन: संगठनों को जैव विविधता से संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना।



गोडलीलॉक्स इकॉनमी

वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 'गोडलीलॉक्स स्थिति' में है।

अर्थव्यवस्था की गोडलीलॉक्स स्थिति क्या है?

- अवधारणा: यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी आदर्श स्थिति को दर्शाता है जहाँ न तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और न ही बहुत धीमी हो रही होती है।
- इस स्थिति की प्रमुख विशेषताएं:
 - अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर बहुत कम होती है।
 - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगातार वृद्धि होती है और कंपनियाँ भी बेहतर आय अर्जित करती हैं।
 - खुदरा मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं।
- गोडलीलॉक्स परिदृश्य निवेशकों के लिए अच्छा होता है क्योंकि कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन करती हैं और शेयर बाजार में तेजी आती है।



वेरा सी. रुबिन वेधशाला (Vera C. Rubin Observatory)

वेरा सी. रुबिन वेधशाला ने ब्रह्मांड की अपनी पहली तस्वीरें जारी की हैं।

वेरा सी. रुबिन वेधशाला के बारे में

- यह वेधशाला चिली में स्थित है। यह लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम (LSST) नामक परियोजना को संचालित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- LSST दक्षिणी गोलार्ध की मैपिंग करने वाली 10 वर्षीय परियोजना है।
- इस वेधशाला का नाम खगोलविद वेरा सी. रुबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डार्क मैटर के अस्तित्व का अग्रणी प्रमाण प्रदान किया था।



SPREE योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी 196वीं बैठक में नियोक्ताओं/ कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली योजना (SPREE) को फिर से शुरू करने की मंजूरी प्रदान की।

SPREE योजना के बारे में

- शुरुआती सफलता (2016 में शुरू हुई): इस योजना ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण में मदद की थी।
- नवीनीकृत SPREE (2025): नई योजना के तहत गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए कर्मचारियों के लिए एक एकमुश्त नामांकन विंडो खोली जाएगी।
- यह योजना दण्डित करने के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर केंद्रित है।
- ESIC को बेहतर बनाने के अन्य निर्णय
- एमनेस्टी स्कीम 2025 (2025-2026) को मंजूरी: इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।
- संशोधित ESI आयुष नीति: इसके तहत ESIC अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्म परिचारक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।



जेलीफिश

केरल के कोचीन बैकवाटर में जेलीफिश का सीजनल यानी मौसमी आक्रमण, पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत है।

जेलीफिश के बारे में

- प्रकार: यह निडारियन समूह से संबंधित है। इसमें कोरल्स और एनीमोन्स भी शामिल हैं।
- पर्यावास: ये महासागरीय जीव हैं जो खुले महासागरों (उष्णकटिबंधीय से आर्कटिक तक) में पाए जाते हैं। इनकी तैरने की क्षमता कम होती है इसलिए ये जलधाराओं की मदद से तैरते हैं।
- विशेषताएं:
 - शिकार पकड़ने और आत्मरक्षा के लिए इनकी त्वचा में डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं।
 - इनका शरीर लगभग 95% पानी से बना होता है, जिससे ये पानी में आसानी से छिप जाते हैं।
 - ये कम ऑक्सीजन (हाइपोक्सिक) वाले वातावरण को भी सहन कर सकते हैं।

जेलीफिश ब्लूम क्या है?

- समुद्री या लवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में जब जेलीफिश की आबादी में अचानक विस्फोटक वृद्धि होती है तो उसे जेलीफिश ब्लूम कहा जाता है।
- यह गर्म समुद्री सतह के तापमान, यूट्रोफिकेशन (जलाशयों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि), अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण के कारण होता है।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची